BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 30th September 2016 | No. 9

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 90वें स्थापना दिवस समारोह
के अवसर पर महामहिम उप-राष्ट्रपति ने कहा–

"बिहार बन सकता है पूर्वोत्तर का गेटवे"

दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। उनकी दाँयीं ओर महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री रामनाथ कोविन्द। बाँयीं ओर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

दिनांक 9 सितम्बर 2016 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का 90वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह का उद्घाटन महामहिम उप-राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री रामनाथ कोविन्द, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।

महामहिम उप-राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के चैम्बर प्रांगण में प्रवेश करते ही उनके स्वागत हेतु प्रतीक्षारत माननीय मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, चैम्बर के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने बूके देकर उनका स्वागत किया और उन्हें मंच तक लेकर आये। महामहिम उप-राष्ट्रपति के मंच पर आगमन होते ही तालियों की गूंज एवं मिलिट्री बैण्ड की राष्ट्रीय गीत की धुन से पूरा हॉल गुंजायमान हो उठा। मंच पर आसीन होने के बाद चैम्बर अध्यक्ष ने अर्केरिया के पौधे भेंट कर महामहिम उप-राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं अति विशिष्ठ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ हुआ।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि उद्यमिता की भूमि बिहार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 90वीं स्थापना दिवस पर महामहिम उप-राष्ट्रपति जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए कोटिश: आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम आज के आयोजन में आपकी शिरकत से बिहार का औद्योगिक व व्यावसायिक समुदाय अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

महामहिम, आपकी गरिमामयी उपस्थित ने न सिर्फ हमारा मान बढ़ाया है अपितु हमारे बीच एक नयी ऊर्जा का संचार भी किया है और आज हम एक बार पुन: बिहार की गौरवशाली गाथा में व्यवसाय एवं उद्योग के नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए प्रेरित व कृत-संकल्पित हैं।

इस शुभ अवसर पर अपनी व्यस्त दिनचर्या से अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति ही हमारी हौसलाअफजाई है।

इस संस्था की स्थापना दिनांक 9 सितम्बर 1926 को बिहार एण्ड उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से की गयी थी, जिसको तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बिहार एण्ड उड़ीसा पोलिटिकल विभाग के पत्रांक 4530 पी. दिनांक 21 दिसम्बर, 1926 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी।

महोदय, आज चैम्बर की स्थापना को 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपके द्वारा इसकी 90वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। यह वर्षगांठ समारोह अगले दो माह तक विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों,

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

सर्वप्रथम मैं आप सबों को चैम्बर के 90वें स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह आप सदस्यों के कृपापूर्ण सहयोग से ही सम्भव हो पाया है। अतः मेरा आभार स्वीकार करें। भावी कार्यक्रमों में भी आपकी इसी प्रकार की भागीदारी की अपेक्षा है।

आपको जानकारी होगी की GST पर महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और इसपर अग्रेतर कारवाई शुरू हो चुकी है। पूरी उम्मीद है कि 1 अप्रैल, 2017 से GST लागू हो जायगी।

दिनांक 9 सितम्बर, 2016 से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2016 एवं स्टार्ट–अप पॉलिसी लागू कर दी गई है। ऐसी उम्मीद है कि ये नीतियाँ भी पुरानी औद्योगिक नीतियों की तरह ही निवेशकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करेगी।

दशहरा एवं दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका

ओ० पी० साह

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

कार्यशालाओं के द्वारा चलाया जाना प्रस्तावित है और इसका समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तावित है।

मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज देश के उद्यमियों व व्यवसायियों की शीर्ष संस्था फिक्की के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

नौ दशकों के लंबे काल–खण्ड में चैम्बर ने काफी उतार–चढ़ाव भी देखे, व्यावसायिक समुदाय के हितों के लिए लंबा, सार्थक व सकारात्मक संघर्ष किया, बिहार की आर्थिक बेहतरी के लिए सदैव अपनी पूरी ताकत झोंकी, खुशहाल व समृद्ध बिहार ही चैम्बर का ध्येय व लक्ष्य रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा।

गौरवान्वित करने वाले इस पल में, इस महती आयोजन में, विशिष्ठ जनों से भरे इस सभागार में मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश व प्रदेश बिहार का नाम रौशन करने वाले ख्याति–लबद्ध उद्यमियों जिनका बिहार और देश के आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान रहा है, का सम्मान महामहिम उप–राष्ट्रपति जी के कर–कमलों से प्रस्तावित है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं चैम्बर की तरफ से हमारे दिवंगत अध्यक्षों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने चैम्बर को इस मुकाम तक पहुँचाने में महती भूमिका अदा की है। साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारे तीन पूर्व अध्यक्षों का भी अभिनन्दन करता हूँ।

इस कड़ी में मैं यहाँ उपस्थित सुधी–जनों को ये बताना चाहता हूँ कि नौ दशकों के सफर में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद को 42 गुणी–जनों ने सुशोभित किया है, इस लंबी फेरहिस्त में विभिन्न सम्मानों व उपाधियों से अलंकृत राजा, महाराजा, जमींदार व प्रसिद्ध उद्योगपति भी शामिल रहे हैं, इसी श्रृंखला में मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी अपनी सेवा चार कार्यकालों में देने का अवसर प्राप्त हुआ है।

अपनी स्थापना से लेकर आज तक चैम्बर ने सरकार और व्यवसायियों एवं उद्यमियों के बीच सेतु की भूमिका निभाई है। सिर्फ सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना तक ही चैम्बर ने कभी अपने आप को सीमित नही रखा बल्कि समालोचक की भूमिका निभाते हुए बिहार के आर्थिक विकास हेतू सरकार के प्रयासों को फलीभूत करने में पूरक की भूमिका अदा की। जनहित और विकासोन्मुखी सद्प्रयास ही चैम्बर का दायित्व है, महज उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के हितों की बातें करने तक ही चैम्बर सीमित नहीं है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश की उन्नति के साथ–साथ राष्ट्र–निर्माण ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का मूल–मन्त्र है। नब्बे सालों की विस्तृत ऐतिहासिक गौरव–गाथा इसकी गवाह है। इसी कड़ी में चैम्बर द्वारा ''कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम'' के अन्तगर्त चैम्बर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं बच्चियों के कौशल विकास हेतु सिलाई–कढ़ाई, क्वील्ट बैग, मेंहदी एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिनांक 8 फरवरी, 2014 से नि:शुल्क चलाया जा रहा है। अभी तक करीब 1000 महिलाओं एवं बच्चियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बिहार में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना में मगध स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना में चैम्बर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सरकार के शीर्ष पदों पर आसीन रहें मूर्धन्य शख्सियतों व नामचीन उद्योगपतियों का मार्ग–दर्शन व आर्शीवाद प्राप्त हुआ है। अनेक अवसरों पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की उपलब्धियों और प्रयासों की अनेकों महामहिम राष्ट्रपतियों, माननीय प्रधानमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और उद्योग–जगत की हस्तियों ने सराहना की है। ऐसी तमाम हस्तियों का अपने परिसर में स्वागत करने का सौभाग्य चैम्बर को प्राप्त हुआ है।

देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत–रत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी उपस्थिति से 1951 में चैम्बर के रजत–जयन्ती समारोह की शोभा बढ़ाई थी। पटना उच्च–न्यायालय के मुख्य–न्यायाधीश स्व० कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह जी 1986 में चैम्बर के स्वर्ण–जयन्ती समारोह के मुख्य अतिथि थे। साल 1976 में हीरक–जयन्ती समारोह में तत्कालीन उप–राष्ट्रपति श्री आर० वेंकेट रमण जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई थी। स्व० वी० वी० गिरी जी, पूर्व राष्ट्रपति एवं स्व० इंदिरा गाँधी जी (पूर्व प्रधानमंत्री) की मेजबानी करने का सुअवसर भी चैम्बर को प्राप्त हुआ है।

महामहिम, अब मैं बिहार के वर्तमान आर्थिक परिदृष्य पर प्रकाश डालना चाहूँगा। महामहिम, विकास की दिशा में हमारे सूबे की सरकार के अथक प्रयासों की गाथा से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रदेश बिहार ने विकास के नए मापदण्ड, नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। सर्वांगीण आर्थिक विकास व समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के सरकार के प्रयासों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सकारात्मक सहयोग कर रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की न्याय के साथ विकास की अवधारणा ने राज्य में कानून का राज कायम कर शांति व सौहार्द का वातावरण कायम किया है, जिसके फलस्वरूप विकास के नए रास्ते उभर कर सामने आये हैं। समावेशी विकास के लिए दृढ–संकल्पित मुख्यमंत्री जी की सुशासन की अवधारणा ने पूरी दुनिया में बिहार और बिहारियों को एक नयी पहचान दी है। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सूबे के चहुंमुखी विकास के लिए सतत् प्रयासशील है। आज बिहार में कानून का राज है और अपराधियों के बीच कानून का डर।

मुझे ये बताते हुए भी अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चैम्बर के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे मॉरिशस और चीन गए सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित अनेकों समितियों में चैम्बर को प्रतिनिधित्व दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार, साधुवाद।

महामहिम, प्रदेश में औद्योगिक विकास को नयी दिशा देने के लिए बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 लागू की थी और आज एक बार फिर से इस गरिमापूर्ण मंच से मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि औद्योगिक नीति 2011 देश की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति थी। देश के अनेक राज्यों ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का अनुकरण किया है और इससे प्रेरणा लेकर अपनी औद्योगिक नीतियाँ तय की हैं।

यहाँ इस बात का जिक्र करना अहम् है कि पिछले करीब 10 वर्षों में अनेकों औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है और इसमें 12500 करोड़ का निवेश हुआ है। इन इकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) लोगों को रोजगार हासिल हुआ है। राज्य सरकार निवेश का अनुकूल माहौल प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार के नये रास्तों के सृजन के लिए सतत् प्रयासरत् है। बिहार आर्थिक व समावेशी विकास की नयी राह पर चल पड़ा है और अगर केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है तो इसमें कोई शक, कोई किन्तु-परन्तु की गुंजाईश नहीं है कि सन् 2020 तक बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगा।

अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति- 2016 एवं स्टार्ट-अप पॉलिसी की घोषणा की गयी है। ऐसी उम्मीद है कि ये नीतियाँ भी पुरानी औद्योगिक नीतियों की तरह हीं निवेशकों विशेषकर युवा पीढ़ी को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करेगी।

महामहिम, बिहार के विभाजन के फलस्वरूप खनिज सम्पदा एवं औद्योगिक ईकाईयाँ बिहार से पृथक हो गयीं और आर्थिक व औद्योगिक पिछड़ापन बिहार के हिस्से में आया। इसको ध्यान में रखते हुए ही सूबे की सरकार ने केन्द्र सरकार से बिहार को औद्योगिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है जो हरेक बिहारी की मांग है।

महामहिम, संतोषप्रद पहलू ये है कि उच्च आर्थिक एवं औद्योगिक विकास दर हासिल करना हमारे प्रदेश की सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। आर्थिक विकास की नयी उँचाईयाँ हासिल करने के लिए हमे कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। सूबे में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। अगर हम सुनियोजित तरीके से इन संभावनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तो हरित-क्रांति का लक्ष्य हासिल करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। खाद्य-प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पूरे देश में बिहार से उपयुक्त परिस्थितियाँ कहीं और नहीं है। बिहार में श्रम-शक्ति के साथ-साथ कच्चे माल की प्रचुरता है।

महामहिम, किसी संस्था के लिए अपनी स्थापना के नब्बे वर्षों के व्यापक व विस्तृत काल-खण्ड को सफलतापूर्वक तय करना गौरव की बात है। राज्य एवं देश समाज की सेवा के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के लिए अपने सहयोग व समर्पण का समुचित मूल्यांकन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

अपने नब्बे सालों के प्रभावी सफर की गाथा पर हमें हर्ष तो है लेकिन हम संतुष्ट होकर आराम से बैठने वालों में से नहीं है अपितु उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हुए हम और सुनहरे व स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रयासरत् होने के लिए कटिबद्ध हैं। कई कार्य-कालों में मुझे इस गौरवशाली संस्था का अध्यक्ष बनने का सम्मान हासिल हुआ है और मेरे लिए ये संस्था मेरे शरीर के अभिन्न अंग के समान है। आज के इस विशेष दिवस पर एक बार पुनः मेरी कामना है कि इस संस्था का भविष्य इसके भूत व वर्तमान से भी ज्यादा सुनहरा हो और हमारी ये संस्था उद्योग व व्यवसाय की बेहतरी के साथ-साथ बिहार के विकास की गाथा में योगदान करने के नए प्रतिमान स्थापित करे। बिहार और बिहार के लोगों की सेवा के प्रति हमारा समर्पण पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बने तभी हमारी सार्थकता साबित होगी।

महामहिम, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के प्रति आभार शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना संभव नहीं है, अन्तःकरण से आभार प्रकट करना बिहार की परम्परा रही है और उसी परम्परा का निर्वहन करते हुए मैं एक बार पुनः चैम्बर के इस मंच के माध्यम से समस्त बिहार के उद्यमी एवं व्यवसायियों की ओर से इस उम्मीद के साथ आपका और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति आभार प्रेषित करता हूँ कि भविष्य में भी आप सबों का आर्शीवाद व मार्ग-दर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। उद्यमी-सृजनशील बिहार..... जय बिहार.....जय जय बिहार..... जय हिन्द..... जय बिहार।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए उद्यमियों से बिहार में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि No Risk, No Gain, जोखिम तो उठाना पड़ेगा। बिहार के बाहर काम कर रहे उद्यमी भी राज्य में निवेश करें। कोई भी देश या राज्य बिना उद्योग के विकसित नहीं हो सकता। अपनी बंद मुठ्ठी खोलिये और पूंजी लगाइये।

उन्होंने कहा कि जहाँ अधिक अंडर वर्ल्ड है, वहाँ उद्योग कैसे बढ़ रहा है।

समारोह को संबोधित करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

बिहार में कानून का राज है और किसी भी आपराधिक घटना पर पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से तुरंत कार्रवाई करती है। कुछ डेस्क पर बैठे लोग कमरे में बैठक कर रिपोर्ट जारी करते हैं। यहाँ कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लागू नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से व्यवसायियों को काफी फायदा होगा। यह बिहार में नये उद्योगों की शुरूआत करने हेतु काफी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि पर लोगों की निर्भरता कम हो इसके लिए जरूरी है कि उद्योग धंधे का विकास किया जाये। बिहार में जिस गति से उद्योगों का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। बिहार उपभोक्ता प्रदेश है तथा हम चाहते हैं कि राज्य में उद्योगों का विस्तार हो। सूबे मे युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पॉलिसी भी लागू की गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर रेडिमेड गारमेन्ट्स तैयार करते हैं। अगर यह उद्योग बिहार में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कपड़ा सेक्टर, आई० टी० तथा खाद्य सेक्टर के क्षेत्र में सूबे में काफी संभावनाएँ है। बंगलादेश ने इसी रेडिमेड गारमेन्टस के सहारे काफी तरक्की की है। उन्होंने बिहार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप पॉलिसी और पाँच सौ करोड़ के बेंचर कैपिटल की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के जमीन निबंधन से लेकर स्टाम्प ड्युटी तक को माफ कर दिया है। निवेश हेतु बैंक से लिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर सब्सिडी की व्यवस्था की जा रही है। आप उद्योग लगाएँ किसी तरह की समस्या नहीं होगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 75वें स्थापना दिवस समारोह पर जारी डाक टिकट को याद किया और कहा कि यहाँ कई विभूतियों का आगमन हो चुका है। चैम्बर के लोगों की सरकार की कई कमीटियों में प्रतिनिधित्व है और इनके सुझावों पर सरकार अमल करती है। हाल ही में नालन्दा विश्वविद्यालय के खण्डहर को यूनेस्को की ओर से धरोहर क्षेत्र घोषित करने और महामहिम उप-राष्ट्रपति जी के वहाँ जाने पर उनके प्रति आभार जताया। नब्बे वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा कि अपनी यात्रा के 90 वर्षों में चैम्बर ने सरकार और व्यवसायी समुदाय के बीच एक मजबूत सेतू का काम किया है। यह सरकार की नीतियों को अपनाता है जो बिहार के आर्थिक विकास में अनुकूल है। चैम्बर ने प्राकृतिक

समारोह को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द।

आपदाओं के समय जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की है।

समाजिक, आर्थिक चिंताओं के मोर्चे पर, यह साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए काम किया है। 8 फरवरी 2014 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अपने प्रांगण में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है और अब तक इस प्रशिक्षण केन्द्र से 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता के कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। 90 वर्षो के कार्यकाल में चैम्बर ने कई सराहनीय कार्य किये हैं। व्यवसाय क्षेत्र से अलग सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए चैम्बर सराहना का पात्र है। इसके साथ ही उन्होंने 90 वर्ष पूर्ण होने पर चैम्बर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

बिहार के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए महामहिम उप-राष्ट्रपति मो० हामिद अंसारी ने कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर मौजूदा समय में बिहार का योगदान देश में अहम भूमिका निभा रहा है। नदियाँ, उपजाऊ भूमि और युवाओं के इस प्रदेश में इन संसाधनों का बेहतर उपयोग जरूरी है। बिहार के युवाओं का उपयोग बेहतर तरीके से हो, इसके लिए इनका कौशल विकास जरूरी है।

महामहिम उप-राष्ट्रपति ने कहा है कि बिहार में निर्माण, सार्वजनिक सेवाएँ व संचार के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अगर पिछले दशक की रफ्तार बरकरार रही तो बिहार पूर्वात्तर भारत का गेटवे बन सकता है। मौजूदा दर को कम से कम दो दशक तक बरकरार रखना होगा तभी बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा।

महामहिम उप-राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक निवेश का वातावरण बनाए रखना होगा। विदेशी निवेश के लिए शांति, कानून की सर्वोच्चता और कानून के आगे बराबरी भी जरूरी है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कानून एक जरूरी स्तंभ है। सही कानून ही बाजार बनाता है। विशाल बहुमत से जीतकर बनी बिहार सरकार समावेशी विकास और नीतियों के बल पर अपने उद्देश्यों को पाने में कामयाब होगी।

महामहिम उप-राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित राज्यों की श्रेणी में आने के लिए बिहार को और काम करने होंगे। बिहार विधानमंडल में पेश आर्थिक सवेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने ये बातें कहीं।

महामहिम ने कहा कि 2005-06 से 2014-15 के बीच बिहार ने सलाना 10.5 फीसदी की दर से विकास किया है, जो कई बड़े राज्यों से अधिक है। निर्माण, संरचना, बीमा व बैंकिंग के क्षेत्रों में तो इसकी प्रगति 15 फीसदी से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय 7914 रुपये से 15 हजार 640 रुपये हो गए। देश के विकास में योगदान 2.6 प्रतिशत से 3.3 फीसदी हुआ। 15वें से 14वें स्थान पर यह राज्य आया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुखद भविष्य की उप-राष्ट्रपति ने कामना की और कहा कि भविष्य में भी यह सरकार और व्यवसायी के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता रहेगा।

इस अवसर पर वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, के० के० बिड़ला ग्रुप ऑफ शुगर कम्पनीज के चेयरमैन श्री चन्द्रशेखर नोपानी, अलकेम फार्मास्युटिकल्स लि० के फाउन्डर चेयरमैन श्री सम्प्रदा सिंह, टाईम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री विनीत जैन और आईटीसी के चेयरमैन श्री वाई० सी० देवेश्वर को महामहिम उप-राष्ट्रपति द्वारा 90 वर्ष के उपलक्ष्य मे बनाये गये चैम्बर के मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

उपर्युक्त उद्यमियों में श्री सम्प्रदा सिंह की अनुपस्थिति में उनके पुत्र श्री सतीश कुमार सिंह ने, आईटीसी के चेयरमैन वाई० सी० देवेश्वर की जगह आईटीसी के एक्जीक्युटिव वाईस प्रेसिडेन्ट श्री नजीब आरिफ ने एवं श्री विनीत जैन की जगह टाईम्स ग्रुप के श्री केशव प्रधान ने सम्मान ग्रहण किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने महामहिम उप-राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री को चैम्बर का मेमेन्टो एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री पन्नालाल खेतान एवं श्री मोतीलाल खेतान, सांसद श्री हरिवंश, मेयर श्री अफजल इमाम, विधायक श्री विजय कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद श्री गंगा प्रसाद, भारत सरकार के सेवा निवृत सचिव श्री अफजल अमानुल्लाह, पूर्व मंत्री श्रीमती परवीन अमानुल्लाह, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री आनन्द किशोर, जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, वाणिज्य-कर आयुक्त श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव उद्योग डॉ० एस० सिद्धार्थ, महिला आयोग की चेयर पर्सन श्रीमती एन० विजयालक्ष्मी, केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, बिहार एवं झारखण्ड के चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनो के प्रतिनिधिगण, चैम्बर के माननीय सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण सहित प्रेस एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का मंच संचालन महामंत्री श्री शशि मोहन ने किया।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् आयोजन सम्पन्न हुआ।

Speech by Shri M. Hamid Ansari, Honourable Vice president of India at the event to mark the 90th Anniversary of the Bihar Chamber of Commerce and Industry in Patna on 9th September 2016.

समारोह को संबोधित करते महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी।

I am happy to be here today in your midst. Bihar has had a place of pride in India's history, played a critical role in the freedom movement, and continues it today as an important state in the Union of India.

Allow me to offer my condolence to the people affected by the ravages of floods in the past few weeks. I am confident that the efforts of the government and the resilient spirit of the people of Bihar will prevail and they will come out of the ordeal stronger.

In not too distant past, Bihar was one of the most prestigious and prosperous regions of India. Blessed by fertile lands and bountiful rivers, endowed with diverse resources, and with a rich tradition of fine handicrafts; it was a commercial hub in eastern India, and in the 17th and 18th centuries attracted European colonizers coveting its riches.

The Bihar Chamber of Commerce and Industry, thus, is an inheritor to a rich commercial history. Starting as the Bihar and Orissa Chamber of Commerce in 1926, it is the 5th oldest chamber in India. And today, as the Chamber celebrates its 90th anniversary, I offer my felicitations and good wishes for future successes.

The last decade has seen remarkable growth in Bihar. The 10th Bihar Economic Survey Report- 2015-16, which was tabled before the Bihar Legislature in February this year by the Government of Bihar, stated that the state economy has grown annually at 10.5% during the period 2005-06 to 2014-15, highest among all major Indian states. Some sectors, such as Manufacturing, Construction and Insurance & Banking grew at over 15%. The per capita income in Bihar has also increased from Rs. 7914 to Rs. 15640 in the same period. The contribution of the state to Indian economy has also increased from 2.6 to 3.3%.

Impressive as these gains are, these have to seen in the context of the small economic base to begin with. States like Haryana and Goa have outperformed Bihar. Bihar still has one of the lowest per capita income levels in the country and lags behind Madhya Pradesh by 10 years and India by 15 years[2]. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) data show that state's economy was the 14th largest in the country in 2014-15, having moved up one spot from the 15th position it occupied in 2004-05.

The progress made by Bihar in areas of construction, public services, and improved telecommunication have been the key drivers in this spurt of growth. But the state needs to expand economic growth and maintain its rapid tempo for at least two decades if it aspires to join the league of developed states.

Bihar also has tremendous potential in the agricultural sector given its natural advantage such as a highly fertile soil, access to water from several rivers for irrigation and warm climate. I am informed that the government is pursuing a 'Rainbow Revolution', akin to the Green Revolution, that can change the face of Bihar's agriculture if it is implemented well throughout the state.

No less important is the demographic dividend that must be reaped by Bihar with increased focus on education and skill development, for both boys and girls.

This audience knows well that business is conducted best under conditions of peace, stability and good governance. An essential ingredient of proper governance and therefore of economic prosperity is Rule of Law that has three ingredients: (a) the absolute supremacy of regular law (b) equality before the law (c) access to justice and development of law by the judges on a case by case basis. Its purpose is avoidance of tyrannical laws or their execution in a tyrannical manner. This approach has been upheld in judicial pronouncements with the Supreme Court describing the Rule of Law as 'a potent instrument of social justice to bring about equality in results.'

In the context of private investments, the 'rule of law' establishes rules that people—and businesses—must follow to avoid being penalized. The rule of law not only allows people to understand what is expected of them in their personal capacities but also sets forth rules for businesses so that they, too, know what is expected of them in their dealings and transactions. In addition, it restrains government and others from infringing on property rights. Should disputes arise, the rule of law provides a peaceful and predictable means by which those disputes can be resolved.

This principle is endorsed universally today. The G8 Foreign Ministers in their Declaration on the Rule of Law in 2006 characterized it as the principle of supremacy of the law, equality before the law, accountability to the law, legal certainty, procedural and legal transparency, equal and open access to justice for all, irrespective of gender, race, religion, age, class, creed or other status, avoidance of arbitrary application of the law and eradication of corruption.

The existence of rule of law is an essential pre-requisite for creating an environment that supports economic growth and draws foreign investments. The law is a necessary foundation for the promotion of business because the legal rules of a country create the marketplace. The establishment and implementation of a fair and predictable set of legal rules is vital to business formation as well as the acquisition and protection of property rights.

Maintaining law and order will thus be essential to attracting investments for rapid growth. Bihar has to create an environment where more businesses see Bihar as a gateway to consumers in the eastern part of the country and as a place where cost of setting up a plant will be competitive with an abundant supply of workers.

I am confident that the government, with its impressive mandate and focused on inclusive development, is devoting its policies and energies to attain these objectives.

Nor can the external environment be neglected. We are now living in a globalised world. The existence of standardized and harmonized commercial laws provides certainty and predictability for international business. Thus, the work of the World Trade Organisation (WTO), the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) and the Hague Conference on Private International Law cannot be overemphasized. They are important in developing uniform rules for the international marketplace.

Countries desiring to have a share of international business must be prepared to adopt conventions and model laws that the major trading nations have already implemented as part of their law. The adoption of such uniform law can create an enabling environment to facilitate international trade and investment.

The most direct and visible link between international legal obligations, the rule of law and investor confidence is demonstrated by the emergence and rapid proliferation of the modern Bilateral Investment Promotion & Protection Agreements or BIPAs, which bridged the substantive divide between the positions of capital investors with respect to fair and equitable treatment, due process protections against expropriation, and other features.

Such Agreements protect the interests of investors and increase their comfort level by assuring a minimum standard of treatment in all matters and provide for justifiability of disputes with the host country. Since 1960, nearly 3,000 such instruments have been negotiated. Almost all of these Agreements include access to the neutral arbitration of disputes.

As part of the Economic Reforms Programme initiated in 1991, the foreign investment policy of the Government of India was liberalized and negotiations undertaken with a number of countries to enter into BIPAs. Government of India have, so far, signed BIPAs with 83 countries out of which 72 have already come into force. Agreements are also being negotiated with a number of other countries. Our experience has been that BIPA encourage foreign investors to invest in a State and there by contributing towards overall developments and advancements of the economy.

Looking ahead, I believe that the local Chambers of Commerce has an important role to play in fostering innovation and competiveness in Bihar. The Chamber can act as a conduit for business to government interface, as also the nodal point for increasing the interactions between businesses and research institutions to help transmit innovations and new technologies into the industries.

I am certain that the Bihar Chamber of Commerce and Industries will leverage its vast experience and history to successfully play this part.

I wish you all the very best for your 90th Anniversary celebrations.

Jai Hind.

समारोह की झलकियाँ

महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी एवं चैम्बर के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पन्ना लाल खेतान।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

महामहिम उप राष्ट्रपति को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन।

महामहिम उप राष्ट्रपति को अर्केरिया का पौधा भेंट कर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को अर्केरिया का पौधा भेंट कर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अर्केरिया का पौधा भेंट कर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को अर्केरिया का पौधा भेंट कर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

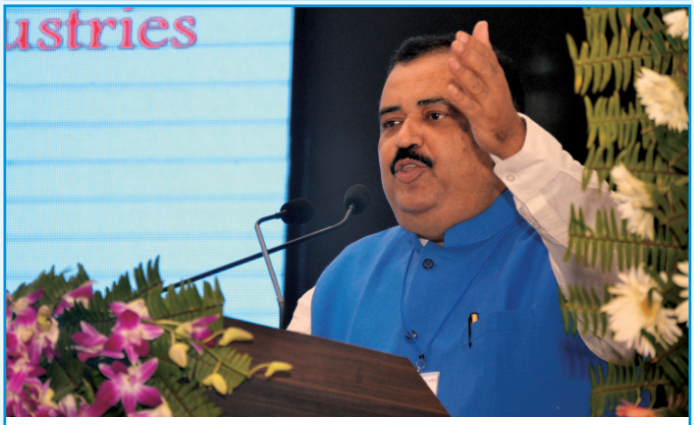

समारोह का मंच संचालन करते चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

वेदांता रिसोसेज के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल को मेमोन्टो प्रदान कर सम्मानित करते महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी।

के० के० बिड़ला ग्रुप ऑफ सुगर कंपनी के चेयरमैन श्री चन्द्रशेखर नोपानी को मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी।

महामहिम उप राष्ट्रपति से अलकेम फर्मास्युटिकल्स लि० के संस्थापक चेयरमैन श्री सम्प्रदा सिंह का सम्मान ग्रहण करते उनके पुत्र श्री सतीश कुमार सिंह।

महामहिम उप राष्ट्रपति से टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री विनित जैन का सम्मान ग्रहण करते श्री केशव प्रधान।

महामहिम उप राष्ट्रपति से आईटीसी के चेयरमैन श्री वाई० सी० देवेश्वर का सम्मान ग्रहण करते आईटीसी के एक्जीक्युटिव वाइस प्रेसिडेन्ट श्री नजीब आरिफ।

महामहिम उप राष्ट्रपति को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

महामहिम उप राष्ट्रपति को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को शॉल भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

समारोह समापन के समय राष्ट्रगाण पर खड़े सम्मानित अति विशिष्ट अतिथिगण एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण।

महामहिम उप राष्ट्रपति के प्रस्थान के समय सम्मान में खड़े सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

चैम्बर के पश्चिमी लॉन में कार्यक्रम को देखने हेतु लगाये गये पंडाल में दर्शक दीर्घा एवं एलसीडी।

दोपहर के भोजन में सम्मिलित सम्मानित अतिथिगण।

दोपहर के भोजन में सम्मिलित सम्मानित अतिथिगण।

चैम्बर की आगंतुक पुस्तिका में अंकित महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के आशीर्वचन

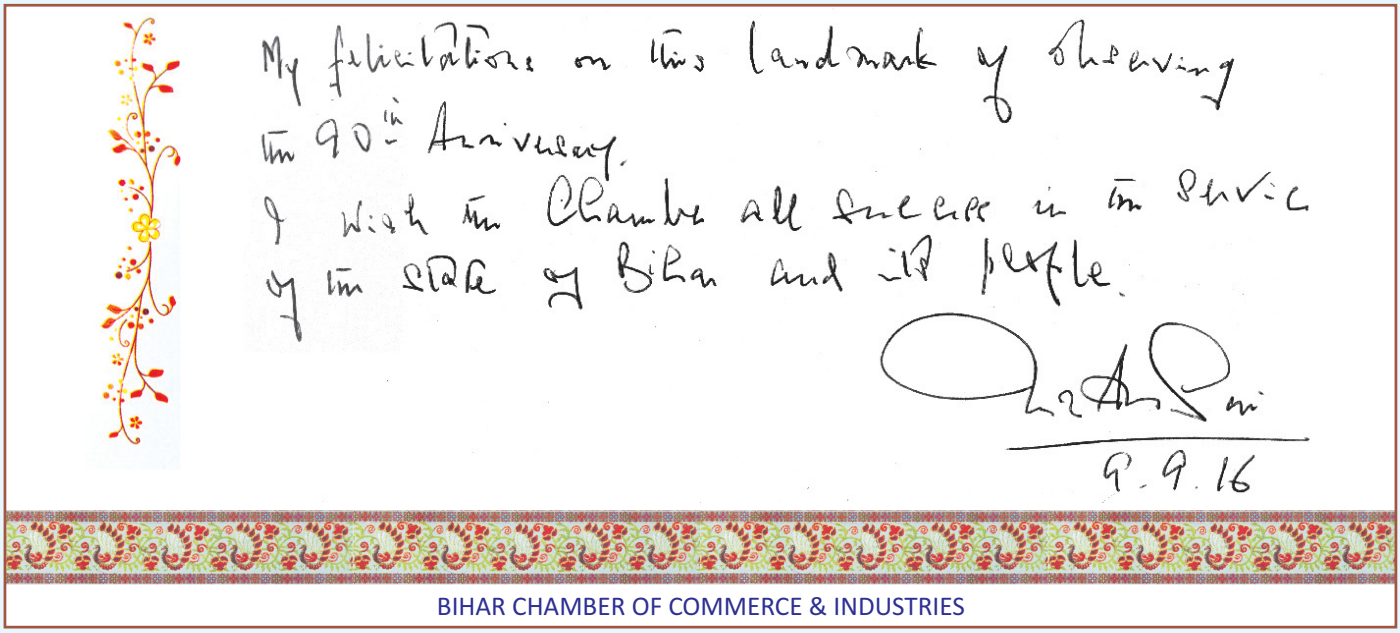

कपड़ा उद्योग पर टिकी बिहार की नजर

बिहार सरकार अब राज्य में परिधान उद्योग को लुभाने में जुट गई है। राज्य सरकार ने इस उद्योग को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल किया है, जिसमें निवेशकों को ज्यादा रियायतें और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, सरकार औद्योगिक पार्कों में जमीन भी प्राथमिकता पर देने को लेकर विचार कर रही है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों ने बिहार में अपनी इकाइयाँ लगाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी नीतियाँ काफी अच्छी हैं। हम कंपनियों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास आज इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में प्रशिक्षित मानव संसाधन भी है। रेशम से लेकर कपास तक हर प्रकार के कपड़ों के लिए कच्चा माल भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। वहीं, हमारे पास अच्छा-खासा बाजार भी है, इसलिए बिहार में कई दिग्गज कपड़ा कंपनियों ने अपनी इकाइयां लगाने में रुचि दिखाई है।'

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेशकों को उनकी लागत की 30 फीसदी रकम ब्याज अनुदान के रूप में देने का फैसला किया है। उद्योग विभाग की ओर से उद्यमियों को उनके निवेश के शत प्रतिशत के बराबर कर की प्रतिपूर्ति भी होगी। वहीं, गैर प्राथमिक उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने यह सीमा 70 फीसदी रखी है। हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वस्त्र बनाने वाली कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा था, 'कपड़ा उद्योग में ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इस वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ बिहार में हैं। यहाँ निफ्ट है, कारीगरों की बड़ी तादाद है। रेशम है और सूत भी बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा, बिहार से कोई भी कंपनी पूर्वोत्तर और मध्य भारत के बाजार तक आसानी से पहुँच सकती है।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.9.2016)**

सरकार वहन करेगी पेटेंट पर आने वाला खर्च

बिहार के स्टार्ट-अप उद्यमी अगर अपने किसी आइडिया को देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराएगे, तो इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उद्योग विभाग ने युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए शैक्षणिक एवं व्यवसायिक शिक्षण के संस्थानों में उद्यमिता सहायता केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया है। साथ ही औद्योगिक पार्क या इंडस्ट्रियल हब में स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए 10 फीसद स्थान सुरक्षित रखने का भी फैसला लिया है। पेटेंट के संबंध में उद्योग विभाग ने फैसला किया है कि अगर कोई स्टार्ट-अप उद्यमी अपने आइडिया को, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी प्रदान हो चुकी है, देश में पेटेंट कराना चाहता है तो उसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। अगर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पेटेंट कराएगा तो उसपर आने वाले खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। पीपीपी मोड में स्टार्ट-अप के लिए संयुक्त आधारभूत संरचना स्थल का निर्माण भी कराया जाएगा। स्टार्ट-अप उद्यमी इसकी सुविधा तीन वर्षों तक मुफ्त ले सकेंगे।

राज्य सरकार ने जो स्टार्ट-अप नीति तैयार की है, उसमें नए उद्यमियों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने पर जोर है। परन्तु कोई निजी निवेशक अगर ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगा तो उद्योग विभाग उसे 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया कराएगा। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार उद्यमियों को हर नई पहल से अवगत कराएगी, साथ ही समस्याओं से अवगत होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 13.9.2016)**

उद्योगपतियों ने की सीएम से मुलाकात

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज के कार्यक्रम में भाग लेने आये उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके। अणे मार्ग स्थित आवास में मुलाकात की। इस औपचारिक मुलाकात के दौरान वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, केके बिरला ग्रुप ऑफ कम्पनीज के चेयरमैन सी० एस० नोपानी, एलकेम फार्मास्यूटिकल के संस्थापक चेयरमैन सम्प्रदा सिंह के पुत्र सतीश कुमार सिंह, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज के प्रेसिडेंट ओ० पी० साह, पूर्व प्रेसिडेंट पी० के० अग्रवाल चैम्बर के उपाध्यक्ष एम० एन० बरेरिया, सीआईआई के चेयरमैन एसपी सिन्हा शामिल थे।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है और राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 लागू किया गया है। बिहार में आधार भूत संरचना एवं बुनियादी ढांचे में अब कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप सभी उद्योगपति राज्यहित के लिये कुछ बड़ा निवेश करने की मंशा बनायें। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.9.2016)**

Interview of business magnets with Times of India on 9.9.2016.

"Proposals should be viable as well"

Anil Agrawal
Vedanta Resources Chairman

- **The CM has specially implored you to invest in Bihar. What are your plans?**

We are definitely thinking about it. Our work is mostly in oil and gas, copper, zinc and iron ore sector. We are open to investing between Rs50 and Rs50O crore in mineral processing in Bihar. We will also think about setting up some higher education institutes as well. We will also build 4,000 'Nand Ghar', upgraded Anganwadis, majority of which would be in Bihar

- **Tell us about your Bihar connect.**

We are committed to bringing a positive change in Bihar. I feel personally indebted to the state and will like to repay, but that cannot be done only on sentiments; the proposals need to be viable as well.

- **What measures Bihar needs to attract more investors?**

Good infrastructure, power connectivity, adequate water, land and cheap labour are the basic requisites for establishing any industry.

- **Your comments on total prohibition in Bihar.**

The whole world has appreciated CM Nitish Kumar's determination in implementing the ban. The move is definitely a plus in the direction of women empowerment in Bihar.

"Law & order, infra primary concerns"

S. K. Singh
Son of ALKEM Lab Chairman
Samprada Singh

- **Tell us about your Bihar connect**

Anything I say about Bihar will be less. I keep coming to the state and its good to be back to the roots.

- **What changes are you noticing in Bihar?**

A lot of changes are visible. Infrastructure and power sectors have, of course, seen lots of improvement. Some investment also seems to have come to the state in recent years.

- **Any plan to invest in Bihar?**

The CM has mentioned it at today's event. He has talked about the state government's new policies. We will definitely think about it. It will be kind of payback to the state.

- **Which sectors would you like the government to work on to attract investors?**

There are a number of things on which Bihar has to catch up to be on par with developed states. Law and order and infrastructure are the two primary concerns. It will take some time but the state is moving steadily on the path of progress.

- **Bihar has become a dry state. Your comments?**

Lots of thinking must have gone before the government took the decision. We welcome the government's move and hope it will have a positive effect on the state.

Need to focus on healthcare sector

C. S. Nopany
Birla Sugar Chairman

- **Your Bihar connect and future investment plans for the state?**

We are into sugar business and are already working in the cane rich regions in Bihar. Our investment here is to the tune of Rs400 crone. We closely work with the farmers and have plans to increase out-sugar cane crushing capacity. In future, we may think of expanding our business in Bihar.

- **Your observation on the 'change in Bihar' over the last few years.**

Bihar has undergone a tremendous change during the last decade or so. Some of the visible areas of improvernent are infrastructure, roads, power and law and order. However, a lot more ground has to be covered and it will take some time to develop Bihar.

- **What more can be done to attract investments in the state?**

Much has been done but the state needs to focus on bettering its soft infrastructure now. Education is a major sector; schools, colleges and universities in rural areas need to be developed. As also the healthcare sector, especially in villages and smaller towns. A further thrust on social infrastructure will be good to attract more people to Bihar, as those who come to work here look for these facilities and it makes their stay longer.

"ITC interested in food processing"

Nazeeb Arif
ITC Executive Vice President

- **Tell us about your Bihar connect**

We are in Bihar for over a hundred years now with our cigarette factory at Munger. We have ventured into the dairy sector as well in that district. We are producing 50,000 litres against a plant capacity of 2 lakh litres. ITC also train rural women in incense stick-making.

- **Elaborate on your plans for business diversification in the state.**

We are planning to foray into food processing industry and will come up with an integrated consumer goods manufacturing unit, either at Hajipur or in Samastipur. We are also in production of new varieties of wheat for our flour brand. We are also tying up with a company for litchi juice.

- **What difference do you notice In Bihar over the last few years?**

The difference is in the government being proactive and taking the right steps in the right direction. The chief minister is enthusiastic about furthering the state's development and we are taking a leap of faith placing our trust in him.

- **Your thoughts on total prohibition in Bihar.**

Every state has to look into its own social and cultural environment. I will not like to make any comments about it, but we will try to look for prospects in hospitality sector as well. **(Source : T.O.I. 10.9.2016)**

वेदांता बनाएगा अल्युमीनियम पार्क

वेदांता रिसोर्सेस के चेयरमैन तथा दुनियाभर में मेटल किंग के रूप में ख्यात अनिल अग्रवाल ने कहा कि घर में सम्मान मिलने का आनंद बड़ा होता है। मुम्बई, लंदन, अमेरिका समेत कई देशों में कई सम्मान मिले, लेकिन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पटना में मुझे जो सम्मान दिया है, उससे भावुक हूँ। यह अवार्ड मेरा नहीं, पूरी दुनिया में काम कर रहे और राज्य का नाम रोशन कर रहे समस्त बिहारियों का है।

उप राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पाने के बाद श्री अग्रवाल मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। अच्छा वातावरण, कनेक्टिविटी, पर्याप्त पानी और बिजली, सस्ता लेबर और सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध है। बिहार में मजबूत सरकार है। निवेश को लेकर खूब प्रचार-प्रसार

होना चाहिए। भारत को जिंक, लेड, कॉपर, एल्युमीनियम, चाँदी, धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले श्री अग्रवाल ने कहा कि उनकी योजना बिहार में अल्युमीनियम पार्क स्थापित करने की है। 50 से 500 करोड़ तक की इंडस्ट्री प्लान कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक धन है। श्री अग्रवाल ने कहा कि हिन्दुस्तान में गरीबी दूर करने के लिए नीचे तक देखना होगा। हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक धन है, लेकिन 40 फीसदी से अधिक धन आयात में चला जाता है। 85 फीसदी तेल हम बाहर से खरीदते हैं। एजुकेशन सेक्टर में बड़े निवेश की जरूरत है। देशभर में 15 फीसदी शिक्षक भारत के और उनमें ज्यादातर बिहार के हैं। श्री अग्रवाल ने घोषणा की कि वेदांता समूह बिहार में भी एक विश्वविद्यालय खोल सकता है।

4000 आंगनबाड़ी को नंदघर बनाएंगे : अनिल अग्रवाल ने बताया कि देश में चल रहे 13 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4000 का जिम्मा वेदांता समूह ने लिया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इनमें ज्यादातर संख्या में बिहार के आंगनबाड़ी केन्द्र उन्हें दिए जाएं। आंगनबाड़ी केन्द्रों को माडर्न लुक देकर वे नंदघर में तब्दील करेंगे, जहाँ प्रीपेक फूड, मेडिकल चेकअप और टीवी के माध्यम से शिक्षा की सुविधा होगी।

दस वर्षों में काफी बदल गया बिहार : नोपानी

के० के० बिड़ला ग्रुप ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सीएस नोपानी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में काफी बदलाव आया है। बिजली, सड़क अस्पताल और स्कूल सहित अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है।

यही कारण है कि अब उद्यमी बिहार आने की बात फिर से सोचने लगे हैं, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, उन क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम है। वैसे भी कोई भी काम धीरे-धीरे ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि किसी चीज को तोड़ना या बिगाड़ना आसान होता है, लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के विकास के लिए जो पहल शुरू की है वह निश्चित रूप से न सिर्फ उद्यमियों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि यहाँ उद्योग लगने से कई लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे।

उन्होंने बताया कि एक समय था, जब उद्यमी बिहार में कारोबार करना तो चाहते थे, लेकिन कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाने की बात नहीं सोचते थे। अब बिहार में बदलाव शुरू हो गया है। बिहार में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.9.2016)

90 साल का हुआ देश का 5वाँ सबसे पुराना चैम्बर

चैम्बरों की स्थापना	
कोलकाता	1830
चेन्नई	1836
मुम्बई	1836
कोचिन	1857
बिहार	1926
फिक्की	1927
गुजरात	1949
दिल्ली	1950

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश का पाँचवाँ सबसे पुराना चैम्बर है। इसकी स्थापना 9 सितम्बर, 1926 को हुई थी। तब इसका नाम बिहार एंड ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। वर्ष 1936 में बिहार से ओडिशा अलग हो गया। इसके बाद 1937 में इससे चैम्बर से ओडिशा को अलग कर दिया गया। इस तरह इसका नाम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। पुन: सन् 2012 में इसका नाम बदलकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हो गया क्योंकि यह व्यापार के अलावा उद्योगों के हितों की भी रक्षा करता है। यह संस्था भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। चैम्बर अपने 90 साल के इतिहास के दौरान न सिर्फ राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। एक आर्थिक रूप से मजबूत बिहार तथा व्यापार व उद्योग के विकास में इसका अहम योगदान है।

1925 में चैम्बर की जरूरत हुई थी महसूस : बिहार चैम्बर की शुरुआत महज 19 सदस्यों के साथ हुई थी। यह आज उद्यमियों व व्यवसायियों का एक शीर्ष संगठन बन चुका है। बिहार के प्राय: सभी प्रमुख व्यापार और उद्योग के लोग इससे जुड़े हुए है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से प्रताड़ित ओडिशा और बिहार के व्यापारियों व उद्योगपतियों को वर्ष 1925 में चैम्बर की जरूरत महसूस हुई।

रुपया और पाउंड का विवाद मुख्य वजह : चैम्बर की स्थापना के पीछे रुपया और पाउंड के अनुपात का विवाद मुख्य कारण था। चैम्बर के प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर राघा कृष्ण जालान एवं मानद सचिव आर० सी० पंडित बनाये गये। 21 दिसम्बर 1962 को तत्कालीन सरकार के अपर सचिव ने इसकी विधिवत मान्यता दी। चैम्बर का पहला कार्यालय बैंक ऑफ बिहार के कार्यालय भवन में खोला गया, जिसका विलय अब भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हो गया।

उद्योगपतियों को एकजुट करना मुख्य मकसद : चैम्बर की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य श्रम, परिवहन, कराधान व चुनौतियों का सामना करने में व्यापारियों और उद्योगपतियों को एकजुट करना था। चैम्बर में अपने स्थापना काल से सफलता पूर्वक राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों की सेवा करते हुए वर्ष 1951 में सिल्वर जुबली मनाया। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। वर्ष 1976 में मने गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीएन सिंह ने किया। वर्ष 1986 में चैम्बर के डायमंड जुबली समारोह के मुख्य अतिथि तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमण रहे। वर्ष 2002 में चैम्बर के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में भरत रत्न तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने भाग लिया था। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

> "बिहार चैम्बर अपने स्थापना काल से ही राज्य के उद्यमियों तथा सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता आ रहा है। यह न केवल राज्य के उद्यमियों व व्यवसायियों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि समय-समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार को अपने बहुमूल्य सुझावों और सलाह से भी अवगत कराता है।" **– शशि मोहन,** महासचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : प्रभात खबर, 9.9.2016)

Bihar Bizman Has 11% Market Share In Logistics Sector

2-Wheeler Dealer Now Transports 1.2 L Mobikes/Mth

From a petty third-party logistics services involving five to six trucks in the 1980s to a multi-crore logistics superpower with 11 % market share, Khaitan Logistics Private Limited has earned for its proprietor, Bihar-born the coveted tag of a go-getter. So impressed was Nitish Kumar when he met the Commerce grad at the 90th anniversary function of Bihar Chamber of Commerce and Industries in Patna on 9.9.2016 that the CM in his address at the function made a special reference to him. "His story should be told to people," the CM said.

Recalling that BCCI President 0. P. Sah introduced P. L. Khaitan to him as a Bihari who has now shifted to Jaipur, the CM told the audience that Khaitan, however, had insisted that he was still living in Bihar. "Such people should pay back by way of business investments in their home state." the CM said.

Indeed, Khaitan's firm has its HQ in Jaipur although he has a residence in Patna. It was in Patna that he ventured into business with a two-wheeler dealership around 40 years ago. "At that time I would ask myself how two-wheelers could be transported from the assembly line to dealers without the bikes getting a single scratch," the sexagenarian recalled, explaining how he got the idea of venturing into logistics operations.

Khaitan started with a small team of four people. "In the 1980s, outbound logistics for factories was a new concept. A major challenge was to get a transport permit from every state through which my trucks were to cross." he said and added nowadays one could thankfully have an all-India permit through a single window.

PRIDE OF PATNA : Khaitan Logistics has today 1,500 trucks, carrying 1.2 lakh two-wheelers from factories to dealers in several parts of the country every month. The business magnate laughed off a question about his firm's turnover, but said, "Most of the 200 and odd existing logistics providers in the country operate with ten to twelve trucks. Also, our market share in this particular logistics sector is ten to 11%."

Bihar, according to Khaitan, has good business potential in automobile sector as it is one of the largest consumers. "At least 55,000 two-wheelers are delivered in Bihar every month. Financers also willingly lend finance because people of the state by and large are famous for their repayment culture'," he said. **(T.O.I., 11.9.2016)**

स्मार्ट पटना को व्यवसायियों ने दिखाई एकजुटता

परिचर्चा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः प्रमंडलीय आयुक्त श्री आनन्द किशोर एवं महामंत्री श्री शशि मोहन। दाँयीं ओर क्रमशः हिन्दुस्तान के वरीय स्थानीय संपादक डॉ० तीरविजय सिंह, हिन्दुस्तान के बिजनेस हेड श्री शैवेश वर्मा, एच० आर० हेड (हिन्दुस्तान) श्री रवि शंकर एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया।

पटना को स्मार्ट बनाने के लिए हिन्दुस्तान अखबार द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सभागार में दिनांक 21 सितम्बर 2016 को एक परिचर्चा हुई। परिचर्चा में शहर के उद्यमियों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे।

ये आए महत्वपूर्ण सुझाव : • नए निर्माण में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू किया जाए • फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडिग जोन बनाने की जरूरत • पैन सिटी सॉल्यूशन के लिए ट्रासपोर्ट एण्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट • ठोस कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता से लागू किया जाए।

पटना को स्मार्ट बनाने में शहर के उद्यमियों ने पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। शहर के उद्यामियों ने कहा कि अपने शहर को कौन स्मार्ट बनाना नहीं चाहेगा। इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। यह एकजुटता उन्होंने आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सभागार में आयोजित परिचर्चा में दिखाई।

चैम्बर के सदस्यों ने पटना को स्मार्ट और बेहतर शहर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने इनमें से कई सुझावों को स्मार्ट पटना के प्रस्ताव में शामिल करने का आश्वासन दिया। इससे पहले आर्किटेक्नो एजेंसी ने स्मार्ट पटना के लिए तैयार प्रस्तावों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया।

लोगों को जगाने का प्रयास : हिन्दुस्तान के वरीय स्थानीय संपादक डॉ. तीरविजय सिंह ने कहा कि जिस पटना में रह रहे हैं। उसके लिए कुछ करने और बेहतर बनाने के लिए पटनावासियों को जगाने का प्रयास है। इसके लिए अलग-अलग वर्गों, समुदायों के बीच जाकर हिन्दुस्तान प्रयास कर रहा है। पटना को स्मार्ट बनाना नागरिकों, पदाधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी चुनौती है। बिहार में सीतामढ़ी जैसे धार्मिक और राजगीर जैसे ऐतिहासिक शहर मौजूद हैं। बावजूद अवसर की उपलब्धता के कारण लोग पटना में बसना ज्यादा पसंद करते हैं। जहाँ अवसर है, वहाँ सुविधाएं देनी होंगी। व्यवसाय और व्यवसायी वर्ग जहाँ जीवंत होते हैं, वहाँ शहर अपने आप जीवंत होता है। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। पटना को बेहतर बनाने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। कार्यक्रम में हिन्दुस्तान के बिजनेस हेड शिवेश वर्मा, एचआर हेड रवि शंकर सिंह मौजूद रहे।

ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रैफिक मैनेजगेंट को शीर्ष वरीयता : प्रमंडलीय आयुक्त

प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट को शीर्ष वरीयता दी जाएगी। जाम से निजात के लिए शहर में कई नई पार्किंग खुलेंगी। अभी जहाँ पार्किंग है, वहाँ सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर उसका उठाव किया जा रहा है। मौर्यालोक में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए कार्ययोजना बनेगी। मल्टीलेवल पार्किंग को एलिवेटेड पुल से स्टेशन तक जोड़कर, यहाँ जानेवाले रास्ते को पूरी तरह से जाममुक्त किया जाएगा। पटना सिटी के कुछ सड़कों को वन वे किया जाएगा। पटना के न्यू मार्केट में निगम की भूमि है। वहाँ की सभी दुकानों को ध्वस्त कर बड़े आधुनिक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा।

कौन नहीं चाहेगा राजधानी पटना बने स्मार्ट : ओ. पी. साह

चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि पटना स्मार्ट बने। दुनिया में सभी लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं। पहले हम नागरिकों को स्मार्ट बनना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा। उसके बाद शहर को स्मार्ट बनाने में सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत रामाचक बैरिया में कचरा निष्पादन इकाई और डोर-टू-डोर कचरा उठाव कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। यह भी कहा कि ट्रैफिक जाम पटना का नासुर बन गया है। अगर कोलकाता और बनारस जैसी तंग गलियों वाले शहर को जाममुक्त बनाना जा सकता है तो पटना को क्यों नहीं। उन्होंने कचरा उठाव कार्य रात में कराने का सुझाव नगर आयुक्त को दिया।

जल्द शुरू होगा घरों से कचरा उठाव का काम : नगर आयुक्त

नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि सभी वाडों में जल्द घर से कचरा उठाव कार्य शुरू होगा। एजेंसियों के टेंडर में रुचि नहीं दिखाने के कारण निगम को सफलता नहीं मिली है। निगम 155 छोटे ऑटो टिपर व कई हाथ ठेला खरीद रहा है। कुछ एजेंसियों से कचरा उठाने के लिए बात चल रही है। सफलता नहीं मिली तो अपने संसाधनों से ही काम शुरू किया जाएगा। फुटपाथी दुकानदारों के लिए 18 वेंडिग जोन चिह्नित किए गए हैं। एक अक्टूबर से रामाचक बैरिया में एजेंसी कचरा लेना शुरू कर देगी। इसके बाद शहर की सफाई बेहतर होगी। पटना को स्मार्ट बनाने में उन्होंने चैम्बर और नागरिकों से सहयोग मांगा और निगम संबंधी समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया।

स्मार्ट बनाने के लिए सुरक्षित करना होगा शहर

पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले इसे सुरक्षित शहर बनाना होगा। स्मार्ट का मतलब है कि सुरक्षा, मोबिलिटी (गतिशीलता) ऑल वेल कनेक्टेड (सारी सुविधाएँ आपस में जुड़ी हों), रिस्क फ्री सिटी (खतरा रहित शहर) और टेलीकम्यूनिकेशन। ये हुआ स्मार्ट का फुल फॉर्म। स्मार्ट सिटी के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम जरूरी है। टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं से लोगों को स्मार्ट सोल्यूशन मिलना चाहिए। दूसरा पहलू है गतिशीलता। यानी लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सुविधा विकसित किया जाए, ताकि लोगों को कहीं भी जाने में परेशानी न हो। तीसरा वेल कनेक्टेड। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खतरा रहित शहर बनाना होगा। अंत में टेलीकम्यूनिकेशन और इंटरनेट। वर्तमान समय में हम इसके बिना स्मार्ट बनने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए टेलीकम्यूनिकेशन और इंटरनेट की बेहतर और सुव्यवस्थित इंतजाम करना होगा।

चैम्बर सदस्यों ने खुलकर रखी बात

स्मार्ट सिटी योजना ऊपर के बजाय नीचे से शुरू होनी चाहिए। यातायात, मॉल, सिनेमा हॉल, सड़क, कूडा उठाने की उचित व्यवस्था हमें स्मार्ट सिटी की ओर ले जाएगी। **– शशि मोहन,** महासचिव, बीसीसीआई

"महावीर मंदिर से जीपीओ गोलबर तक यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यू मार्केट में अतिक्रमण इतना अधिक है कि वहाँ के दुकानदारों को परेशानी होती है। अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए।" **– किशोर कुमार अग्रवाल**

"ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार जरूरी है। केवल ट्रैफिक व्यवस्था से ही अधिकतर समस्या दूर हो जाएंगी। एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर उतरने के पास एक गोलबर होना चाहिए।" **– महावीर बिदासरिया**

"शहर को स्मार्ट होने के लिए हम लोगों को स्मार्ट होना चाहिए। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह शहर को साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी स्मार्ट होना चाहिए।" **– मुकेश जैन**

"सबसे पहले आम जनता के साथ-साथ प्रशासन के लोगों को शिक्षित करना होगा। कुछ कड़े कानून भी बनाने होंगे। सही ढंग से कानून का पालन भी करना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं हो।" **– आशीष शंकर**

"गोविन्द मित्रा रोड में अवैध पार्किंग है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। कूड़ा भी समय पर नहीं उठता है। हल्की बारिश में पूरा बाजार नरक बन जाता है। शिकायत भी की गई, पर कोई नहीं सुनता है।" **– सावल राम डूलिया**

"पटना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बाजारों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कभी भी इस बिन्दु पर विचार नहीं करता है।"

– रामचन्द्र प्रसाद

"रोड व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। चाहे वह मेन रोड हो या गली-मोहल्ले के रोड हों। यातायात, बिजली, पानी एवं कूड़ा उठाने की उचित व्यवस्था हो। लोगों के साथ-साथ प्रशासन को भी स्मार्ट होना होगा।"

– ए. एम. अंसारी

"यातायात व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पार्किंग व्यवस्था हो। पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो। गुलबी घाट की भी व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ न बिजली की सही व्यवस्था है और न ही रोड ठीक है।" **– कमल नोपानी**

"ऑटो में मीटर की व्यवस्था की जाए। उसके परिचालन की भी सही व्यवस्था हो। रिक्शा से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जलजमाव, अतिक्रमण, दुकानदारों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।"

– राम अवतार पोद्दार

"रोड के बीच जितने भी चैम्बर हैं उन सभी को ढंक देना चाहिए, ताकि जब भी खोलने की जरूरत पड़े तो उसे आसानी से खोल दें। कई लोगों ने अवैध रूप से नाला जोड़ दिया है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।" **– सच्चिदानंद**

"पटना को कूड़ा उठाने की सही व्यवस्था करनी चाहिए। रोड की व्यवस्था खासकर गर्दनीबाग में काफी खराब है। रोड नंबर एक में हमेशा रिक्शा व ऑटो लगे रहते हैं। जानवर घूमते रहते हैं।" **– उत्पल कुमार सेन**

"पटना सिटी में वन- वे ट्राफिक व्यवस्था होनी चाहिए। सिटी में गाँधी सरोवर की हालत दयनीय है। रोड खराब है। ऑटो का परिचालन सही होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।" **– गोविन्द कनोडिया**

"पटना को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। घर की तरह शहर को साफ रखना होगा। इसमें जिला प्रशासन को कड़े नियम बनाने चाहिए। नियम नहीं मानने वालों को सजा मिलनी चाहिए।" **– सत्यप्रकाश**

"पटना को स्मार्ट बनाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। पार्किंग, यातायात, ऑटो स्टैंड की उचित व्यवस्था करनी होगी। फुटपाथी कारोबारियों के लिए जगह की व्यवस्था होनी चाहिए।" **– अजय गुप्ता**

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.9.2016)

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 के मुख्य बिन्दु

Global Industrial Scenario में तेजी से बदलाव एवं राज्य को Global Industrial Map पर लाने के लिए राज्य में आन्तरिक और देश एवं देश के बाहर से निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में नयी **"बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016" दिनांक 29.8.2016 से अगले पाँच वर्षों के लिए लागू की गयी है।**

इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि सभी इकाइयों को प्राथमिक क्षेत्र एवं गैर प्राथमिक क्षेत्रों में बाँटा गया है।

प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र : 1. खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र 2. पर्यटन प्रक्षेत्र 3. लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र 4. सूचना प्रौद्योगिकी (सेवाएँ एवं विनिर्माण) तथा इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र 5. टेक्सटाईल प्रक्षेत्र 6. प्लास्टिक एवं रबड़ प्रक्षेत्र 7. अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र 8. हेल्थ केयर प्रक्षेत्र 9. चमड़ा प्रक्षेत्र एवं 10. तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की मुख्य विशेषताएँ : • इस नीति के तहत सभी प्रकार के प्रोत्साहन राशि, इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन (Commercial Production) प्रारंभ करने की तिथि से देय होगा • अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, अम्लीय हमला के शिकार व्यक्तियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को सभी प्रकार के प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा (भूमि को छोड़कर) से अतिरिक्त 15% देय होगा • Term Loan नहीं लेने वाली इकाइयों को Interest Subsidy देय नहीं होगा • स्वीकृत परियोजना लागत ही अनुदान राशि का आधार होगा। स्वीकृत परियोजना लागत में जमीन का मूल्य कुल प्रस्तावित निवेश (भूमि को छोड़कर) के 10% से अधिक नहीं होगा • प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कोई झूठी घोषणा की जाती है तो दिए गये प्रोत्साहन की राशि देय तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी • इस निवेश के अन्तर्गत वैसी इकाइयाँ जो प्रोत्साहन योग्य नहीं है वह वंचित सूची (परिशिष्ट-।।) पर परिलक्षित है • वर्त्तमान इकाई या नई इकाई अगर अपने क्षमता का विस्तार आधुनिकीकरण, विशाखन करती है तो वैसी इकाई को नई इकाई को देय प्रोत्याहन मिलेगा।

व्यावसायिक उत्पादन के बाद मिलने वाली सुविधाएं : इस नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक उत्पादन के बाद प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का प्रावधान किया गया है जिसकी कुल अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपये होगी। जबकि विशेष वर्ग के लोगों के लिए यह सीमा रू. 11.50 करोड़ होगी।

1. स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति : • सरकार द्वारा IADA/ BIADA को भूमि आवंटन हेतु कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा • BIADA के बाहर के भूखंड पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के पश्चात् देय होगा।

2. भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति : कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी के भूमि में सम्परिवर्त्तन के लिए लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति व्यावसायिक उत्पादन में आने के बाद की जाएगी।

3. ब्याज अनुदान : Term / Loan लेने वाले इकाइयों को ब्याज दर का 10% या Term Loan का वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम होगा, देय होगा। सूक्ष्म, एवं लघु उद्योगों के मामलों में 12% Interest Subsidy देय होगा।

नोट : अनुदान की अधिकतम सीमा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 30% एवं सामान्य क्षेत्रों की इकाइयों के लिए 15% देय होगा।

अनुसूचित जाति / जनजाति, महिलाओं, युद्ध विधवाओं, अम्लीय हमला के शिकार व्यक्तियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को ब्याज अनुदान, सामान्य

प्रक्षेत्रों के लिए 11.5% एवं प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र के लिए 13.8% देय होगा। प्राथमिक प्रक्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजना लागत (Project Cost) का 34.5% तथा सामान्य प्रक्षेत्रों के लिए 17.25% ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा तय होगी।

4. कर संबंधी अनुदान : नई इकाइयों द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा की गई VAT/CST/Entry Tax का 80% प्रतिपूर्ति (इकाई द्वारा व्यापार से संबंधित करों को छोड़कर यानि सिर्फ उत्पादन देयता कर के विरूद्ध Input Tax credit के समायोजन के बाद शुद्ध देय कर) व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए देय होगा। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्राथमिक क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 100% एवं गैर प्राथमिक क्षेत्र के लिए 70% देय होगा।

नोट : विशेष वर्ग के लोगों के मामलों में राज्य सरकार के खातों में जमा किए गए स्वीकृत VAT/ CST/Entry Tax का 92% प्रतिपूर्ति गैर प्राथमिक प्रक्षेत्र के मामले में स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5% एवं प्राथमिक क्षेत्र हेतु 115% होगा।

5. विद्युत शुल्क में छूट : कैपटिव पावर जेनरेशन (स्व कार्य हेतु विद्युत उत्पादन) या BSPHCL को दिए गए ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क (Electricity Duty) पर शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कलस्टर के लिए प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना अन्तर्गत CFC की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों के Dovetailing की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि एक ही Asset औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना द्वारा आच्छादित नहीं होगें।

7. निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रोत्साहन : निजी औद्योगिक पार्क के प्रर्वतक, पार्क के पूरा होने के उपरान्त ब्याज 10% अथवा वास्तविक ब्याज दर में जो भी कम होगा उस दर पर स्वीकृत परियोजना के 30% तक ब्याज अनुदान के पात्र होगें, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी। प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष निजी औद्योगिक पार्क को 35% ब्याज अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी।

8. विद्यमान नीति संबंधी प्रावधान : संकल्प संख्या-128 दिनांक: 16.1.2006 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव जो नई नीति के प्रभावित तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आयी है, उन्हें यह विकल्प होगा कि वे नई नीति या विद्यमान नीति से अच्छादित होना चाहते हैं। वैसी इकाई जो औद्योगिक नीति 2011 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 31 मार्च, 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन में आना होगा।

नोट : • बिना किसी सारगर्भित मूल्यवर्द्धन शॉर्टिंग, क्लिनींग एवं पैकेजिंग में शुद्ध रूप से संलिप्त प्रसंस्करण इकाई को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत नहीं माना जाएगा • 100 टी. डी. पी. से अधिक के स्थापित क्षमता के खाद्यान प्रसंस्करण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है • लघु संयत्र विनिर्माण करने वाली इकाई जिसका सीधा उपयोग अन्य लघु संयंत्र बनाने वाली इकाइयों में सीधे तौर पर प्रयुक्त होती है वैसी इकाइयों को प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट - II

वंचित सूची

1. Narcotic Drugs निर्माण की इकाई
2. Alcoholic Beverage निर्माण की इकाई
3. तंबाकू आधारित उद्योग एवं
4. एस्बेस्टस निर्माण की इकाई

(साभार : उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना)

बढ़ेगी औद्योगिकीकरण की रफ्तार : चैम्बर

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा है कि इससे सूबे के औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी। इस नीति में प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए उनके पूंजी निवेश के बराबर राजकीय करों के रूप में पाँच वर्षों के लिए जमा की गई रकम की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। औद्योगिक इकाई द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान, कुल निवेश के 10 फीसद तक अथवा दस करोड़ तक की सीमा में अनुदान देने का प्रावधान है। गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में यह छूट की सीमा 15 फीसद होगी, परंतु यह दस करोड़ से अधिक नहीं होगी।

सामान्य श्रेणी के उद्योगों के लिए किए गए पूंजी निवेश का 70 फीसद या पाँच वर्ष, जो भी पहले हो, राजकीय करों के रूप में जमा की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, नई नीति में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.9.2016)

उद्यमियों को 10 लाख तक मदद

• बिहार में स्टार्ट-अप नीति को मिली मंजूरी • 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड गठित • 25 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले उद्योग ही दायरे में आएंगे • 05 वर्ष तक लाइसेंस और पंजीयन की जरूरत नहीं।

कैबिनेट का फैसला : स्टार्ट-अप नीति 2016 को राज्य कैबिनेट स्वीकृति दे दी। इसके तहत नए आइडिया के साथ उद्योग लगाने को इच्छक उद्यमी को दस लाख रुपये (सीट ग्रांट) तक की मदद सरकार देगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्ययता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव मंजूर किए गए। स्टार्ट-अप नीति के तहत नए आइडिया के साथ उद्योग लगाने वालों से आवेदन लिए जाएंगे। आइडिया को स्वीकृत करने के लिए फंड प्रबंधक नियुक्त होंगे, जो बताएंगे कि इस आइडिया को स्टार्ट-अप नीति के तहत लिया जा सकता है या नहीं। उसके बाद उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। एससी-एमटी के लोगों के लिए 22 फीसदी राशि आरक्षित रखी गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस नीति को लाने का मकसद युवाओं को नए आइडिया के साथ उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

और क्या खास है नीति में : • उद्यमियों से आइडिया लेने के लिए राज्य व जिला स्तर पर एक पोर्टल होगा • स्टार्ट-अप की पढ़ाई भी सरकार कराएगी • फंड जारी करने के लिए एक समिति होगी, अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे • उद्यमियों को फंड की व्यवस्था करने के लिए दो फीसदी राशि सहायता मिलेगी

केन्द्र से 30 हजार प्रति माह : केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नए अन्वेशकों को प्राति माह 30 हजार रुपये की मदद देने का फैसला किया है। स्टार्ट-अप को दी जाने वाली राशि भी बढाकर 10 लाख से एक करोड़ रुपये कर दी है। विभाग के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन एवं सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि स्टार्ट-अप के प्रति शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन की शुरूआत की गई। इसमें अन्वेषक को आर्थिक मदद के साथ-साथ प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए सहायता दी जाएगी।

विज्ञापन नीति 2016 को भी मंजूरी : बिहार विज्ञापन नीति 2016 को स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी। एक-दो दिनों के अंदर इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद वर्ष 2008 की विज्ञापन नीति समाप्त मानी जाएगी। नई नीति के तहत सूचना जन-संपर्क विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो विज्ञापन की कीमत तय करेगी। इसके तहत प्रिंट-इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही स्मारिका, कला-संस्कृति-साहित्य पत्रिका, सेटेलाइट केबल चैनल, मोबाइल एप आदि को भी शामिल किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान 7.9.16)**

स्टार्टअप नीति की स्वीकृति का चैम्बर ने किया स्वागत

बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी को हरी झंडी दिखाने का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा है कि इस नीति में नए उद्यमियों को पाँच साल तक लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज से मुक्त रखने का प्रावधान है। इससे युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद देते हुए साह ने कहा है कि युवा वर्ग इस नीति का अधिक से अधिक फायदा लें। **(सा. : दैनिक जागरण, 7.9.16)**

डाक विभाग का टॉल फ्री नंबर शुरू, 1924 पर करें शिकायत

यदि आप डाक विभाग के कामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायत टॉल फ्री नंबर 1924 पर कर सकते है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 13.9.2016)

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

1 September
Shri Bishnu Kr. Sureka
M/s Bharat Sugar Mills Ltd

8 September
Shri Mukesh Kumar
M/s R. G. Softwares & Systems

11 September
Shri Ritesh Singhal
M/s Krishna

12 September
Shri Anil Pachisia
M/s Anil Enterprises

17 September
Shri Pankaj Kumar
M/s Shivam Enterprises

18 September
Shri Vishal Tekriwal
M/s Vidit Enterprises

20 September
Shri Baidyanath Singh
Industries & Commerce Association

21 September
Shri Raj Kr. Khemka
M/s S. K. Mfg. Co

23 September
Shri Umesh Pratap Tibrewal
M/s Hindustan Commerce & Industry

26 September
Shri Sanjay Pd. Singh
M/s Prasad Sales Agency

27 September
Shri Anup Kumar
M/s Kaveri Liquors Pvt. Ltd

28 September
Shri Padmaraj Kr. Jain
Bhojpur Chamber of Commerce & Industries

29 September
Shri Shashi Shekhar Agrawal
M/s Chetna Agencies

30 September
Shri Purnendu Kr. Labh
M/s Husk Power Systems Pvt. Ltd

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।
– शशि मोहन, महामंत्री

पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने पटना का मास्टर प्लान बनाने से लेकर इसके विस्तार तक की योजना को अंतिम रूप देने के लिए महानगर योजना समिति (पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। मेट्रोपॉलिटन कमेटी का चुनाव दो महीने पहले हुआ था। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव की मंत्रिपरिषद ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी।

कमेटी में शामिल है तीस सदस्य : मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक के बाद बताया कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 30 सदस्य हैं। समिति के जिम्मे पटना का मास्टर प्लान बनाने से लेकर शहर के सुनियोजित विकास और विस्तार की जिम्मेदारी होगी। इसे वर्ष 2030 के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। उन्होंने बताया कि समिति पटना के आयोजन क्षेत्र में अधिसूचित इलाकों को शामिल कर मास्टर प्लान बनाएगी। मास्टर प्लान 1167.04 किलोमीटर की परिधि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

यह है पूर्व से अधिसूचित क्षेत्र : उत्तर में मनेर प्रखंड के रामपुर, हल्दीछपरा से होकर गंगा स्थित भू-भाग से होते हुए खुसरूपुर प्रखंड के हरदासपुरबिगहा तक। दक्षिण में बिहटा प्रखंड के नत्थूपुर मथुरामपुर, तरवन होकर नौबतपुर प्रखंड के चैनुपर, पूर्वी क्षेत्र में दौलतपुर तक। इसी प्रकार पूरब में दौलतपुर से जमालपुर दनियावां प्रखंड के किसमिरिया होते हुए हरदासपुरबिगहा तक और पश्चिम में बिहटा प्रखंड के नत्थुपुर से कौरिया, पानी होते हुए उत्तरी छोर पर मनेर प्रखंड के हल्दीछपरा तक।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.9.2016)

पटना से बांद्रा व जम्मूतवी के लिए हमसफर एक्सप्रेस

पटना से बांद्रा (मुम्बई) व जम्मूतवी के लिए हमसफर ट्रेनें चलेंगी। रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हमसफर एक्सप्रेस की घोषणा की थी। इन दो प्रीमियम ट्रेनों की सौगात पटना को मिलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इन ट्रेनों में केवल एसी 3 के कोच होंगे।

पूमरे के सीपीआरओ एके रजक ने बताया कि एक अक्टूबर से जारी होने वाली नई समय सारणी में इन ट्रेनों को शामिल किया जा रहा है। पहली हमसफर ट्रेन पटना से बांद्रा के बीच चलेगी, जबकि दूसरी सियालदह से जम्मूतवी वाया पटना चलेगी। इनको चलाने की तिथि व समय की जल्द घोषणा होगी। इनकी स्पीड राजधानी एक्सप्रेस का मुकाबला करेगी। सुविधाएँ ज्यादा होने के कारण इनका किराया सामान्य ट्रेनों से 20 प्रतिशत ज्यादा होगा। इन ट्रेनों में जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली होगी। सीसीटीवी लगे रहेंगे। आग व धुएं को पकड़ने व उनकी रोकथाम के उपायों से युक्त इन ट्रेनों में कई अन्य सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी।

दो अंत्योदय ट्रेनें भी : दरभंगा से जालंधर व जयनगर से उधना (सूरत) के बीच अक्टूबर से अंत्योदय एक्सप्रेस चलाई जाएगी। जनसाधारण एक्सप्रेस की तर्ज पर चलने वाली इन ट्रेनों का टाइम टेबल भी जल्द जारी किया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.9.2016)

दशहरा एवं दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएँ।
– श्री शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org